



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2011/फाल्गुन 9, 1932

No. 42]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2011/PHALGUNA 9, 1932

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2011

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (चौथा संशोधन) विनियम, 2011 (2011 का 3)

फा. सं. 305-17/2010-क्यूओएस.—भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (v) तथा उप-धारा (1) के खंड (ग) के साथ पठित धारा 36 के अंतर्गत प्राधिकरण को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (चौथा संशोधन) विनियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) के विनियम 1 के उप-विनियम (2) में,—

(क) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) इन विनियमों के विनियम 12, 18, 19, 20, 21 और 22, 21 मार्च, 2011 को प्रवृत्त होंगे।”

3. प्रधान विनियमों के विनियम 17 में,—

(क) उप-विनियम (11) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(11) प्रत्येक एक्सेस प्रदाता, किसी टेलीमार्केटर को पहले से आवंटित किए गए दूरसंचार संसाधनों को 20 मार्च, 2011 से वापस ले लेगा।”

4. प्रधान विनियमों के विनियम 25 में,

(क) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

“(घ) दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) के विनियम 12, 16, 17 और 18 में अंतर्विष्ट उपबंध 20 मार्च, 2011 तक प्रवृत्त रहेंगे।”

आर.के. आर्नल्ड, सचिव

[विज्ञापन III/4/142/10/असा.]

टिप्पणी 1 : प्रधान विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या 305 17/2010-क्यूओएस, दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

टिप्पणी 2 : प्रधान विनियमों को अधिसूचना संख्या 305 17/2010-क्यूओएस द्वारा संशोधित किया गया था तथा ये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 14 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित हुए थे।

टिप्पणी 3 : प्रधान विनियमों को अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस द्वारा पुनः संशोधित (दूसरा संशोधन) किया गया था तथा ये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित हुए थे।

टिप्पणी 4 : प्रधान विनियमों को अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस द्वारा पुनः संशोधित (तीसरा संशोधन) किया गया था तथा ये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 31 जनवरी, 2011 को प्रकाशित हुए थे।

टिप्पणी 5 : व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (चौथा संशोधन) विनियम, 2011 (2011 का 03) के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषणों के नियंत्रण के लिए एक प्रभावी तंत्र का उपबंध करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 जारी किए थे। विनियमों के विनियम 13, 14, 15, 16 और 17, 15 जनवरी, 2011 से क्रियान्वित किए जाने अपेक्षित थे, जबकि विनियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 10 फरवरी, 2011 से क्रियान्वित किए गए थे।

2. दूरसंचार विभाग द्वारा पत्र सं. 16-5/2009-एस. III / (खंड IV) दिनांक 31 जनवरी, 2011 के माध्यम से '140' नम्बर श्रृंखला प्रदान की गई है जिसे मोबाइल नेटवर्क के लिए टेलीमार्केटरों को आवंटित किया जाना है। तथापि, फिक्स्ड नेटवर्क के लिए नम्बर श्रृंखला अभी तक आवंटित नहीं की गई है। टेलीमार्केटरों को फिक्स्ड नेटवर्क के लिए नम्बर श्रृंखला आवंटित किए जाने के लिए गए मामला तात्कालिक आधार पर उठाया गया है। एक्सेस प्रदाताओं ने यह संकेत दिया है कॉल सेंटर्स से उत्पन्न होने वाले उच्च टैरिफ के परिणामस्वरूप ऐसे कॉल सेंटर्स को सभी संसाधन उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। यह आशा की जाती है कि टेलीमार्केटिंग क्रियाकलापों के लिए दूरसंचार विभाग द्वारा फिक्स्ड नेटवर्क से नम्बर श्रृंखला जल्द ही आवंटित की जाएगी। सभी एक्सेस सेवा प्रदाताओं द्वारा टेलीमार्केटर को संसाधनों का आवंटन किए जाने से पूर्व इस नई श्रृंखला का क्रियान्वयन किया जाना अपेक्षित होगा। इस उद्देश्य के लिए एक्सेस प्रदाताओं को उनकी प्रणाली में विन्यास संबंधी परिवर्तन करने तथा नई श्रृंखला का परीक्षण करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। तदनुसार, दूरसंचार अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) के प्रासंगिक उपबंधों में संशोधन किया गया है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2011

The Telecom Commercial Communications Customer Preference (Fourth Amendment) Regulations, 2011 (3 of 2011)

F. No. 305-17/2010-QoS.—In exercise of powers conferred by Section 36, read with sub-clause (v) of clause (b) of sub-section (1) and clause (c) of sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations, namely:

1. (1) These regulations may be called the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Fourth Amendment) Regulations, 2011.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. In sub-regulation (2) of regulation 1 of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (hereinafter referred to as the principal regulations),

(a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :

“(d) Regulations 12, 18, 19, 20, 21 and 22 of these regulations shall come into force on the 21st day of March, 2011.”

3. In regulation 17 of the principal regulations,

(a) for sub-regulation (11), the following sub-regulation shall be substituted, namely :

“(11) Every Access Provider shall withdraw the telecom resources already allotted to a telemarketer from 20th day of March, 2011.”

4. In regulation 25 of the principal regulations,

(a) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely :

“(d) the provisions contained in regulations 12, 16, 17 and 18 of the Telecom Unsolicited Commercial Communications Regulations, 2007 (4 of 2007) shall remain in effect till the 20th day of March, 2011.”

R. K. ARNOLD, Secy.

[ADVT III/4/142/10/Exty.]

Note 1 : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification No. 305-17-2010-QoS dated 1st December, 2010.

Note 2 : The principal regulations were amended *vide* notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 14th December, 2010.

Note 3 : The principal regulations were further amended (second amendment) *vide* notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 28th December, 2010.

Note 4 : The principal regulations were further amended (third amendment) *vide* notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated 31st January, 2011.

Note 5 : The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of Telecom Commercial Communications Customer Preference (fourth amendment) Regulations, 2011 (3 of 2011).

Explanatory Memorandum

The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulation, 2010 (6 of 2010) dated the 1st December, 2010 to provide an effective mechanism

for curbing unsolicited commercial communications. Regulation 13, 14, 15, 16 and 17 of the regulations were implemented with effect from the 15th day of January, 2011, while regulation 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 were implemented with effect from the 10th day of the February, 2011.

2. DoT *vide* letter No. 16-5/2009-AS, III/(Vol. IV), dated 31st January, 2011 has provided '140' number series to be allocated to telemarketers for mobile network. However, number series for fixed network are still not allocated. The matter has been taken up on urgent basis to allocate number series to telemarketers for fixed network. Access Providers have indicated that it will not be possible to provide all the resources to call centres from mobile network only due to high traffic originated from such call centres. It is expected that number series for telemarketing activities from fixed network will be allocated by DoT shortly. This new series will be required to be implemented by all Access Providers before allocation of resources to telemarketer. For this purpose time will be required by Access Providers to change the configuration in their system and test the new series. Accordingly, relevant clauses of The Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010) have been amended.